Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 23-06-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 23 June, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus :** GS 2 : Social Justice	बुनियादी ढांचे की कमी, फंड की कमी से अंग प्रत्यारोपण प्रभावित हो रहा है: रिपोर्ट
Page 01 **Syllabus :** GS 2 : International Relations	अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु स्थलों पर बमबारी की
Page 05 **Syllabus :** GS 2 : International Relations	ईरानी संसद ने होर्मुज जलडमरूमध्य व्यापार मार्ग को बंद करने के लिए मतदान किया
Page 10 **Syllabus :** GS 3 : Indian Economy	धीमी अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी नीतियाँ
Page 10 **Syllabus :** GS 2 : Social Justice	विदेशी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को कैसे प्रभावित करेंगे?
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus :** GS 3 : Indian Economy	वैश्विक संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना

Page 01 : GS 2 : Social Justice

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट (दिनांक 19 जून), जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है, भारत की अंग प्रतिरोपण प्रणाली विशेषकर सरकारी अस्पतालों में मौजूद गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है। नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) द्वारा आयोजित एक समीक्षा बैठक के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और वित्तीय बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है।

Infrastructure deficiencies, shortage of funds affecting organ transplants: report

S. Vijay Kumar
CHENNAI

The report dated June 19 followed a review of organ transplant activities. C. VENKATACHALAPATHY

The organ transplantation programme in India has been crippled by multiple issues, especially insufficient funds, shortage of specialised doctors, and procedural delays, a report released by the Union Health and Family Welfare Ministry dated June 19 revealed.

The report, which followed a high-level meeting of senior health officials to review the status of organ transplantation activities in government hospitals and identify the key challenges, pointed to infrastructure deficiencies, especially a shortage of intensive care unit (ICU) beds and lack of financial support to patients who required lifelong medication that was expensive.

Explaining the bottlenecks and other issues faced by state-owned institutions, the report said only 13,476 kidney transplants were performed, both in government and private hospitals, against the recommended one lakh cases last year. The capacity of government hospitals was not adequate to meet the target of organ transplants and creation of new centres were "definitely" required.

The report elaborated on the lack of facilities in government healthcare institutions, saying a significant number of government hospitals had reported the absence of dedicated infrastructure for organ retrieval and transplantation, including specialised transplant operation theatres and dedicated transplant intensive care units. A critical issue was the shortage of ICU beds, which were essential for maintaining potential brain-stem dead donors. In many trauma centres, beds were unavailable for potential donors due to high patient volume.

Many institutions, including All India Institutes of Medical Sciences, lacked in-house Human Leukocyte Antigen cross-matching laboratory facilities. The dependency on external laboratories was causing significant delays and logistical challenges in the transplantation process.

The report compiled by the National Organ and Tissue Transplant Organisation, which convened the meeting, said the shortage of specialised faculty, coupled with frequent transfer of trained personnel, was disrupting the continuity and establishment of transplant programmes. A major bottleneck was the scarcity of dedicated and trained transplant surgeons, nephrologists, urologists, anaesthetists, neurosurgeons/neurologists, and intensivists within the government hospitals.

Burden on patients

On the paucity of funds, the report said some hospitals had reported inadequate funds to initiate or restart specialised transplant programmes. A significant concern was the high cost of immunosuppressant drugs, which patients must take for life. The financial support available under current schemes was often limited to the first year.

The report "strongly recommended that liver and heart transplantation, including the lifelong cost of immunosuppressants for post-transplant recipients, be comprehensively included under the central Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana [AB-PMJAY] scheme".

पहचान की गई प्रमुख समस्याएँ:

1. **बुनियादी ढांचे की कमी:**
    - सरकारी अस्पतालों में अंग प्रतिरोपण का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। अधिकांश अस्पतालों में:
        - समर्पित प्रतिरोपण ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू नहीं हैं।
        - ब्रेन-स्टेम डेड डोनरों को बनाए रखने की सुविधाएं नहीं हैं।
        - संभावित डोनरों को रखने के लिए ट्रॉमा सेंटर्स में पर्याप्त बिस्तर नहीं हैं।
    - ये कमियाँ सरकारी अस्पतालों की राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण की मांग को पूरा करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित करती हैं।
2. **संख्या और क्षमता की अपर्याप्तता:**
    - पिछले वर्ष केवल **13,476 किडनी प्रतिरोपण** किए गए, जबकि लक्ष्य एक लाख था।
    - सीमित क्षमता और नए केंद्रों की अपर्याप्त स्थापना राष्ट्रीय प्रतिरोपण लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न करती है।
3. **प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी:**
    - प्रतिरोपण-विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञों जैसे ट्रांसप्लांट सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इन्टेंसिविस्ट, एनेस्थेटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की भारी कमी है।
    - प्रशिक्षित कर्मियों के नियमित स्थानांतरण से कार्यक्रम की निरंतरता और स्थायित्व बाधित होता है।
4. **प्रौद्योगिकी और प्रयोगशाला की खामियाँ:**
    - प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एम्स में भी इन-हाउस HLA (ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन) क्रॉस-मैचिंग प्रयोगशालाएं नहीं हैं।
    - बाहरी प्रयोगशालाओं पर निर्भरता के कारण प्रतिरोपण प्रक्रिया में देरी और तार्किक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
5. **वित्तीय बाधाएँ और रोगी पर बोझ:**
    - प्रतिरोपण के बाद **इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं** की जीवन भर की लागत बहुत अधिक होती है।
    - वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएँ आमतौर पर केवल पहले वर्ष का खर्च कवर करती हैं, जिससे रोगी बाद में असुरक्षित हो जाते हैं।
    - कई अस्पतालों में प्रतिरोपण कार्यक्रम शुरू या पुनः शुरू करने के लिए समर्पित धन की कमी होती है।

रिपोर्ट द्वारा दी गई सिफारिशें:

- **आयुष्मान भारत (AB-PMJAY) के साथ नीति एकीकरण:**
    - यकृत और हृदय प्रतिरोपण को तथा प्रतिरोपण के बाद जीवन भर की इम्यूनोसप्रेसेंट दवाओं की लागत को AB-PMJAY योजना के अंतर्गत लाने की सिफारिश की गई है ताकि रोगियों पर बोझ कम किया जा सके।

- **क्षमता निर्माण:**
  - नए प्रतिरोपण केंद्रों की स्थापना और बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं, तथा जनशक्ति विकास में निवेश बढ़ाने पर बल दिया गया है।

शासन और स्वास्थ्य नीति पर प्रभाव:

- **स्वास्थ्य सेवा में समानता:**
  - निजी और सरकारी अस्पतालों की क्षमताओं में असमानता नैतिक और पहुंच से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। सरकारी सेवाओं पर निर्भर गरीब रोगी उपेक्षित रह जाते हैं।
- **स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण:**
  - एक समग्र नीति की आवश्यकता है जिसमें फंडिंग, मानव संसाधन प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और संस्थागत समन्वय शामिल हो।
- **सतत स्वास्थ्य वित्तपोषण:**
  - अंग प्रतिरोपण जैसी उच्च लागत वाली सेवाओं को सार्वजनिक बीमा योजनाओं में शामिल करना अत्यावश्यक है ताकि रोगियों को विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय से बचाया जा सके।

नीति-निर्माताओं के लिए आगे की राह:

- सरकारी अस्पतालों में प्रतिरोपण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए लक्षित धन आवंटित करें।
- प्रोत्साहनों और स्थायित्व तंत्र के साथ एक मजबूत राष्ट्रीय प्रतिरोपण कार्यबल नीति बनाएं।
- प्रतिरोपण से संबंधित सभी खर्चों को, विशेष रूप से दवाओं और देखभाल को, स्थायी रूप से AB-PMJAY योजना में शामिल करें।
- समय की बचत के लिए एक राष्ट्रीय अंग साझाकरण और लॉजिस्टिक तंत्र विकसित करें।

निष्कर्ष:

अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण भाग है, फिर भी यह निरंतर कम फंडिंग, खराब बुनियादी ढांचे, और जनशक्ति की कमी से पीड़ित है। यदि भारत एक सार्वभौमिक, समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाना चाहता है, तो अंग प्रतिरोपण को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है और इसे AB-PMJAY जैसी योजनाओं के तहत समग्र समर्थन प्रदान करना होगा।

UPSC Mains Practice Question

Ques : नीतिगत पहलों के बावजूद, भारत का अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम प्रणालीगत कमजोरियों से ग्रस्त है।" अवसंरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें तथा व्यवहार्य नीतिगत सुधारों का सुझाव दें। **(250 Words)**

Page 01: GS 2 : International Relations

पश्चिम एशिया में तनाव के एक बड़े वृद्धि के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रविवार को ईरान के तीन परमाणु स्थलों — फोर्दो, नतांज़ और इस्फहान — पर हवाई हमले किए, जो कूटनीतिक प्रयासों से सैन्य कार्रवाई की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह हमला इज़राइल-ईरान शत्रुता और परमाणु वार्ता के ठप पड़ने के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कांग्रेस की स्वीकृति के बिना इस हमले को अधिकृत किया गया, जिसने ईरान की तीव्र निंदा और वैश्विक पर्यवेक्षकों की चिंताओं को जन्म दिया है।

U.S. bombs three key Iranian nuclear sites

Attacks crossed a 'big red line', says Iran Minister while asserting the country's right to self-defence

No immediate signs of radioactive contamination following the strikes, says UN nuclear watchdog

There will be 'either peace or tragedy for Iran', says Trump acting without congressional nod

Associated Press
DUBAI

Prompting fears of a wider regional conflict, the United States inserted itself into Israel's war against Iran early on Sunday by dropping 30,000-pound bombs on a uranium enrichment site buried under a mountain, a risky gambit that aimed at destroying the Islamic Republic's nuclear programme after months of failed diplomacy.

The U.S. also fired dozens of missiles, and President Donald Trump said that the combination of strikes "completely and fully obliterated" three nuclear sites. However, U.S. defence officials said an assessment of the damage was ongoing.

The Atomic Energy Organization of Iran confirmed that attacks took place on the Fordow and Natanz enrichment facilities as well as its Isfahan nuclear site, but it insisted that its nuclear programme will not be stopped. Both Iran and the UN nuclear watchdog said there were no immediate signs of radioactive contamination following the strikes.

U.S. Defence Secretary Pete Hegseth said the country does not "seek war" and that the operation would not be "open-ended", though Mr. Trump earlier warned there would be additional strikes if Tehran retaliated. "There will either be peace or there will be tragedy for Iran," said Mr. Trump, who acted without congressional authorisation. Vice-President J.D. Vance, however, said the strikes have given Tehran the possibility of returning to negotiate with Washington.

Hours later, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said the attacks have crossed a 'big red line' adding that the time for diplomacy had passed and that his country had the right to defend itself. Mr. Araghchi said he would be flying to Moscow to coordinate positions with its ally, Russia. "The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression," he told presspersons in Turkiye.

EDITORIAL
» PAGE 8
MORE REPORTS ON
» PAGES 5 & 14

Trump's gambit

The White House says the combination of strikes 'completely and fully obliterated' three nuclear sites in Iran

Fordow: Iran's most **heavily fortified** nuclear site used for uranium enrichment, which is built deep beneath a mountain

Natanz: Largest **uranium enrichment facility** in Iran

Isfahan: Iran's largest **nuclear research site,** which was targeted by Israel 2 times since the crisis began on June 13

War plans: U.S. President Donald Trump and Cabinet members in the White House on Saturday night. AFP

Iranian parliament votes to close Strait of Hormuz

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Iran's parliament, the Majlis, has reportedly approved the closure of the Strait of Hormuz in response to the attacks by the U.S. on Iranian nuclear facilities, the country's state-owned media PressTV reported on Sunday.

The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea, and is one of the world's most important oil trade routes.

FULL REPORT
» PAGE 5

PM calls for 'immediate de-escalation' of conflict

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi spoke with the President of Iran, Masoud Pezeshkian, and called for "immediate de-escalation" on Sunday, hours after the U.S. struck three prominent nuclear sites in Iran. The conversation between the two leaders is significant as it came ahead of an emergency meeting of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, where the U.S. attack on Iran will be the main subject of attention.

FULL REPORT
» PAGE 5

मुख्य घटनाक्रम:

- अमेरिका ने 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए और भूमिगत यूरेनियम संवर्धन स्थलों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागीं।
- ईरान ने इन स्थलों पर क्षति की पुष्टि की लेकिन यह दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम बिना रुके जारी रहेगा।
- संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी (IAEA) और ईरान ने बताया कि इन हमलों के बाद तत्काल कोई रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं हुआ।
- ईरान के विदेश मंत्री ने इन हमलों को "लाल रेखा पार करना" कहा और आत्म-रक्षा की चेतावनी दी।

- ट्रम्प ने कहा कि यदि ईरान ने प्रतिशोध लिया तो आगे और हमले होंगे, और इसे "शांति या त्रासदी" का चुनाव बताया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव:

1. अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और युद्ध शक्ति निगरानी का उल्लंघन:

- कांग्रेस की स्वीकृति के बिना अमेरिका की एकतरफा कार्रवाई ने अमेरिकी लोकतंत्र में कार्यपालिका की अति-शक्ति पर बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।
- इस हमले को, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के अनुमोदन के अभाव में, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन माना जा सकता है।

2. कूटनीतिक चैनलों का क्षरण:

- ईरान द्वारा यह घोषणा कि "कूटनीति का समय समाप्त हो गया है", परमाणु समझौते (JCPOA) की बहाली की संभावनाओं को खत्म कर देती है।
- इससे यूरोपीय या बहुपक्षीय मध्यस्थता के प्रयासों के लिए स्थान भी सीमित हो जाता है।

3. क्षेत्रीय टकराव का बढ़ा हुआ जोखिम:

- ईरान की रूस के साथ समन्वय जैसी कार्रवाइयाँ भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण को और अधिक गहरा कर सकती हैं।
- ईरान या उसके समर्थक गुटों द्वारा संभावित प्रतिशोधी हमलों की संभावना व्यापक पश्चिम एशियाई संघर्ष की आशंका को जन्म देती है।

4. वैश्विक आर्थिक परिणाम:

- इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने से वैश्विक तेल बाजारों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ेगा।
- होर्मुज़ जलडमरूमध्य — जो एक महत्वपूर्ण तेल पारगमन बिंदु है — के पास बढ़ती तनातनी के कारण बड़े आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।

5. परमाणु अप्रसार (नॉन-प्रोलिफरेशन) की चिंताएँ:

- परमाणु स्थलों पर सैन्य हमले, भले ही बिना रेडियोधर्मी प्रभाव के हों, एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- इससे ईरान को गुप्त रूप से संवर्धन प्रयासों को तेज करने की प्रेरणा मिल सकती है, जिससे वैश्विक अप्रसार मानदंड कमजोर हो सकते हैं।

6. अमेरिका की वैश्विक छवि पर प्रभाव:

- यह हमला अमेरिका के विरोधियों को साहस प्रदान कर सकता है और उन सहयोगियों के साथ संबंधों में खिंचाव ला सकता है जो कूटनीतिक समाधान का समर्थन करते हैं।
- यह अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले परमाणु निगरानी और शांति प्रयासों के प्रतिकूल खड़ा करता है।

भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक विचार:

- **भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और निकासी:** ईरान और खाड़ी देशों में हजारों भारतीय कामगार हैं, इसलिए किसी भी संघर्ष की स्थिति में आपात योजनाएँ आवश्यक हैं।
- **तेल और व्यापार पर निर्भरता:** इस क्षेत्र में व्यवधान से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है।
- **संतुलन की नीति:** भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक संतुलन साधना होगा।

निष्कर्ष:

ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हवाई हमलों ने पहले से ही नाजुक पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक नया अस्थिरता स्तर जोड़ दिया है। इन हमलों का उद्देश्य भले ही ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना हो, परंतु यह एक व्यापक संघर्ष को उकसा सकता है, कूटनीति को कमजोर कर सकता है और वैश्विक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों में दूरगामी असर डाल सकता है। भारत जैसे देशों के लिए चुनौती यह है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों का प्रबंधन करते हुए एक ध्रुवीकृत होती दुनिया में रणनीतिक तटस्थता बनाए रखें।

UPSC Mains Practice Question

Ques: ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हवाई हमले कूटनीति से एकतरफा सैन्यवाद की ओर बदलाव को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीयता पर इस बदलाव के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (250 words)

Page : 05 : GS 2 : International Relations

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों के बाद, एक नाटकीय वृद्धि के रूप में, ईरान की संसद (मजलिस) ने दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री चोकप्वाइंट्स में से एक — होर्मुज़ जलडमरूमध्य — को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। हालांकि अंतिम निर्णय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है, यह राजनीतिक कदम सैन्य आक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया में अपने भौगोलिक लाभ का उपयोग करने के तेहरान के इरादे को दर्शाता है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह ईरान और अरब प्रायद्वीप (विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के मुसंदम क्षेत्र) के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है।
- यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- ईरान उत्तरी तट पर स्थित है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात दक्षिणी तट पर है।
- ओमान की खाड़ी जलडमरूमध्य के पूर्व में है, जबकि फारस की खाड़ी पश्चिम में।
- यह जलडमरूमध्य 167 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई 39 किलोमीटर से 95 किलोमीटर के बीच भिन्न होती है।
- इसकी चौड़ाई उत्तर की ओर संकरी होती जाती है, लेकिन फिर भी बड़े जहाजों के पारगमन की अनुमति देती है।
- जलडमरूमध्य में स्थित कुछ द्वीप हैं: हेंगाम, होर्मुज़ और किश्म।

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण चोकप्वाइंट्स में से एक माना जाता है।
- दुनिया की लगभग 30% तरलीकृत गैस और 25% कच्चा तेल इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिसमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारी मात्रा शामिल है।
- किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सकता है, शिपिंग पर असर डाल सकता है, और बीमा एवं माल ढुलाई लागत को बढ़ा सकता है।

प्रमुख प्रभाव:

1. वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर प्रभाव:

- जलडमरूमध्य के बंद होने या उसमें व्यवधान से वैश्विक बाजारों में तत्काल तेल मूल्य अस्थिरता और घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- अल्पकालिक व्यवधान भी विशेष रूप से तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकता है।

2. भारत की रणनीतिक चिंताएँ:

- भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 80% आयात करता है, जिसका अधिकांश भाग इस क्षेत्र से होकर आता है।
- हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आपूर्ति के विविधीकरण और रणनीतिक भंडार की बात कही है, फिर भी भारत कीमतों के झटके और क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है।
- यह जलडमरूमध्य भारत के खाड़ी और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के लिए भी एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है।

3. पश्चिम एशियाई संघर्ष की वृद्धि:

- यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों की और अधिक सैन्य प्रतिक्रिया को उकसा सकता है, जिससे फारस की खाड़ी में खुले संघर्ष का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- पहले से ही नाजुक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को यह गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

4. भौगोलिक स्थिति का रणनीतिक उपयोग:

- ईरान अपने भौगोलिक प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा है — वैश्विक व्यापार मार्ग को बंद करने की धमकी देकर वह सैन्य आक्रमण के खिलाफ अपनी शक्ति दिखा रहा है।
- यह पारंपरिक युद्ध के बिना प्रभाव दिखाने की उसकी क्षमता को पुष्ट करता है, जिससे असममित रूप से तनाव बढ़ता है।

Iranian parliament votes to close Strait of Hormuz trade route

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Iran's parliament, the Majlis, has reportedly approved the closure of the Strait of Hormuz in response to the attacks by the U.S. on Iranian nuclear facilities, the country's state-owned media PressTV reported on Sunday, citing Esmaeil Kowsari, a member of the Majlis.

The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea, and is one of the world's most important oil trade routes.

According to the report, which cited Esmaeil Kowsari, a member of the Majlis, the final decision on the closure of the Strait of Hormuz lies with Iran's Supreme National Security Council.

India imports about 80% of its oil requirement, meaning that disruptions in the Strait of Hormuz will likely impact the price of oil that India purchases. The Strait of Hormuz is also a vital trade route for ships travelling to and from India.

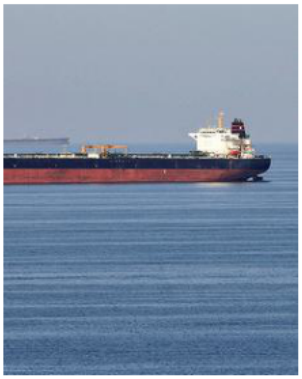

The strait connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the Arabian Sea. FILE PHOTO

Petroleum Minister Hardeep Puri, however, downplayed the impact on India. "We have been closely monitoring the evolving geopolitical situation in the Middle East since the past two weeks," Mr. Puri posted on X. "Under the leadership of PM @narendramodi Ji, we have diversified our supplies in the past few years and a large volume of our supplies do not come through the Strait of Hormuz now." "Our Oil Marketing Companies have supplies of several weeks and continue to receive energy supplies from several routes," he added.

5. कानूनी और कूटनीतिक प्रभाव:

- जलडमरूमध्य को बंद करना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNCLOS) का उल्लंघन हो सकता है।
- इससे अंतर्राष्ट्रीय निंदा हो सकती है और ईरान को संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर और अधिक अलग-थलग कर सकता है।

भारत के लिए नीति विकल्प:

- **कूटनीतिक पहल:** भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संवाद बनाए रखते हुए तनाव कम करने और वार्ता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।
- **ऊर्जा विविधीकरण:** रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के साथ रणनीतिक समझौते करके खाड़ी मार्गों पर निर्भरता को और कम करना चाहिए।
- **समुद्री सुरक्षा सहयोग:** क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ सहयोग करें और हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पहलों में भाग लें।
- **रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाना:** भविष्य के झटकों से बचने के लिए भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) का विस्तार करें।

निष्कर्ष:

ईरानी संसद द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने के प्रस्ताव को पारित करना केवल एक सामरिक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ईरान की भू-राजनीतिक क्षमता का एक रणनीतिक संकेत है। भले ही इसका वास्तविक बंद होना अनिश्चित हो, केवल इसकी धमकी ही वैश्विक बाजारों और कूटनीतिक संतुलन को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। भारत के लिए यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि उसे रणनीतिक दूरदर्शिता, ऊर्जा सुरक्षा में विविधता, और एक मजबूत कूटनीति बनाए रखने की आवश्यकता है — खासकर इस प्रकार के अस्थिर क्षेत्र में।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: होर्मुज़ जलडमरूमध्य भू-राजनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है?

1. इसके माध्यम से वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है।
2. यह प्रशांत महासागर में नाटो बलों के लिए एक प्रमुख नौसैनिक मार्ग है।
3. यह ईरान और ओमान/संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है।
4. इसका उपयोग मध्य एशिया से गेहूं और कोयले के निर्यात के लिए किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 4
D) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

Page 10 : GS 3 : Indian Economy

भारत वर्तमान में एक दुर्लभ स्थिति का अनुभव कर रहा है, जिसमें मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियाँ विस्तारवादी (expansionary) हैं। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती और सरकार द्वारा आयकर में छूट दी गई है। यह नीति संयोजन आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन यह व्यापक आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति प्रबंधन और एक धीमी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय प्रोत्साहन की प्रभावशीलता को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है।

Expansionary policies in a slowing economy

Stable macroeconomic outcomes require co-ordination between fiscal and monetary policy. The effects of expansionary fiscal policy can be nullified through contractionary monetary policy; this occurred in the U.K. and the U.S., where the announcement of tax cuts were met with a reluctance to further cut interest rates

ECONOMIC NOTES

Rahul Menon

The Reserve Bank of India (RBI) has cut key lending rates in two successive meetings, indicating a significant expansionary shift. In April 2025, the repo rate was cut by 25 basis points, and a further 50 basis point cut was announced in the recent meeting in June, bringing the policy repo rate to 5.5%. The RBI forecasts GDP growth of 6.5% for 2025-26, and inflation within the band of 4% +/- 2%, indicating sufficient room for these rate cuts.

The reduction in inflation has allowed for this expansionary move. The expectation is that it will spur private investment and lead to increased growth rates. But these moves have come on the back of a similar expansionary move on the part of fiscal policy, that of the recent cuts in income taxes. The fact that expansionary fiscal policy is being followed by expansionary monetary policy necessitates questions regarding the policy mix.

Policy co-ordination

Both fiscal and monetary policy impact aggregate demand and inflation. By reducing interest rates by way of monetary policy, investments increase and vice versa. An increase in government spending or a reduction in taxes increases aggregate demand and consumption through fiscal policy. Increasing aggregate demand leads to rising demand for goods and services, thereby increasing labour demand and wages, eventually leading to an increase in inflation. Therefore, stable macroeconomic outcomes require co-ordination between fiscal and monetary policy. The effects of expansionary fiscal policy can be nullified through contractionary monetary policy; this occurred in the U.K. and the U.S., where the announcement of tax cuts were met with a reluctance on the part of monetary policy to further cut interest rates, citing the inflationary nature of such fiscal policy moves. When monetary policy becomes ineffective, expansionary fiscal policy is required. In the wake of the 2008 recession, when interest rates had hit zero, government spending was increased to bring full employment.

GETTY IMAGES

Currently, one can characterise both fiscal and monetary policy in India as being expansionary. The income tax cuts announced in February 2025 were forecast to provide a significant boost to the economy. This raises a serious question of economic policy co-ordination. If both policy moves work as they are intended to, it would imply a significant increase in inflation. Does the RBI foresee muted inflation risks even as consumption and investment demand both show an increase? Or has the consumption tax cuts failed to show any impact on output expansion, implying an increase in fiscal deficit in the future?

Muted growth

Inflation fell to a six-year low of around 3% in June, with early monsoons and a good harvest leading to a significant fall in the headline inflation rate. This has provided the RBI with sufficient room for a reduction in the interest rate, though headwinds, such as U.S. President Donald Trump's tariff wars and the growing conflict in Iran, loom on the horizon.

The economy does show signs of weakness. A recent SBI report indicated that credit growth has fallen to a three-year low of 9% in May 2025, while the unemployment rate has risen to 5.6% in May 2025 from 5.1% in April. Coupled with low inflation, these are indicative of an economy facing significant pressures on the aggregate demand front. The standard solution is to cut interest rates to boost investment in the face of slowing demand. What is of concern is the slowdown in the economy after the announcement of the income tax cuts. Households were expected to respond to the windfall gain in their disposable incomes by increasing their spending, thus leading to rising aggregate demand and inflation. On the contrary, though growth is forecast to remain steady at around 6.5%, these indicators show that the momentum might just be flagging.

Once could make the argument that these policies take time for signals to be converted into outcomes. Households may only convert the tax windfall into consumption when it actually materialises. But there are two problems with this argument. Firstly, it violates a central contention that individuals are inherently forward-looking, and can discount future windfalls into current spending. This assumption is central to the theoretical framework underlying modern inflation targeting. Secondly, if individuals are not forward-looking, and will only consume in the future, it would imply a sudden increase in future inflation when both investment and consumption increase, necessitating a sharp reaction for future monetary policy.

Deficit fears

Sufficient cuts to interest rates might provide the boost to the economy that income tax cuts could not. However, there is another problem. If output does not rise sufficiently, it would lead to a fall in tax collections, and a rise in the fiscal deficit. The only way to maintain the deficit is to cut government spending. If the government decides to cut revenue spending and not capital expenditure, the impact might fall on vulnerable populations that depend on such spending. With rising power of monopoly capital and a sustained shift towards profits away from wages, relying on normal market mechanisms may no longer achieve the desired outcomes. Sustained government intervention bringing about increases in wages and consumption power for those at the bottom of society is the need of the hour.

Rahul Menon is Associate Professor at O.P. Jindal Global University.

THE GIST

- Currently, one can characterise both fiscal and monetary policy in India as being expansionary. This raises a serious question of economic policy co-ordination.
- The economy does show signs of weakness. A recent SBI report indicated that credit growth has fallen to a three-year low of 9% in May 2025, while the unemployment rate has risen to 5.6% in May 2025 from 5.1% in April.
- Sufficient cuts to interest rates might provide the boost to the economy that income tax cuts could not. However, there is another problem. If output does not rise sufficiently, it would lead to a fall in tax collections, and a rise in the fiscal deficit.

क्या हुआ है?

- RBI ने रेपो दर में कुल 75 आधार अंकों की कटौती की है (अप्रैल में 25 और जून 2025 में 50), जिससे यह 5.5% पर आ गई है।

- सरकार ने फरवरी 2025 में आयकर कटौती की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू खपत और निजी निवेश को बढ़ावा देना है।
- अच्छे मानसून और खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण जून में मुद्रास्फीति छह वर्षों के निचले स्तर लगभग 3% पर आ गई है।
- इन प्रोत्साहनों के बावजूद, क्रेडिट ग्रोथ गिरकर तीन वर्षों के निचले स्तर 9% पर आ गई है और बेरोजगारी दर मई 2025 में 5.6% तक बढ़ गई है।
- ये संकेतक दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मांग-पक्षीय तनाव (demand-side stress) से जूझ रही है।

प्रमुख मुद्दे और बहसें:

1. नीति समन्वय की दुविधा:
- मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को समन्वय में काम करना चाहिए ताकि उनके प्रभाव बेहतर हों।
- यदि दोनों ही नीतियाँ विस्तारवादी हों, तो अर्थव्यवस्था के ओवरहीट होने का खतरा होता है, जब तक कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में न हो।
- यह स्थिति U.K. और U.S. जैसे पिछले मामलों से मिलती-जुलती है, जहाँ राजकोषीय प्रोत्साहन को मुद्रास्फीति की आशंका के कारण मौद्रिक सतर्कता के साथ संतुलित किया गया।

2. विस्तारवादी नीति की प्रभावशीलता:
- आयकर कटौती से समग्र मांग (aggregate demand) में जो बढ़त अपेक्षित थी, वह अब तक सामने नहीं आई है।
- इसके संभावित कारण:
    - घरेलू उपभोक्ता पूर्वदर्शी नहीं हैं, जैसा कि मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण सिद्धांत मानता है।
    - उपभोग के बजाय बचत में वृद्धि, जो कम उपभोक्ता विश्वास को दर्शाती है।

3. राजकोषीय जोखिम और घाटे की चिंताएँ:
- यदि उत्पादन और कर संग्रह अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ते, तो राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है।
- इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है — विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण जैसे राजस्व व्यय में।
- इससे कमजोर वर्गों पर असमान प्रभाव पड़ सकता है।

4. संरचनात्मक चुनौतियाँ:
- अर्थव्यवस्था में मज़दूरी से मुनाफे की ओर बदलाव हो रहा है, साथ ही एकाधिकार शक्तियाँ बढ़ रही हैं।
- मांग को बढ़ाने के लिए केवल बाजार तंत्र पर्याप्त नहीं रह गए हैं।
- इसलिए, सरकार की लक्षित हस्तक्षेप नीति — विशेष रूप से मज़दूरी और रोज़गार समर्थन में — आवश्यक हो गई है।

भारत की आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ:

- **धैर्य की आवश्यकता:** राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का प्रभाव तत्काल नहीं होता; उनका असर समय के साथ दिखाई देता है।
- **समावेशन पर ध्यान: निम्न-आय वर्ग** की खपत को बढ़ाना **सार्वभौमिक कर कटौती** से अधिक प्रभावी हो सकता है।
- **पूर्वधारणाओं पर पुनर्विचार:** नीति-निर्माताओं को यह मानना बंद करना होगा कि सभी घराने **तार्किक और पूर्वदर्शी** ढंग से कार्य करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में राजकोषीय और मौद्रिक दोनों नीतियों का एक साथ विस्तार एक मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित **करने का मजबूत प्रयास है। हालांकि, तत्काल परिणामों की अनुपस्थिति यह दिखाती है कि** मांग प्रबंधन, नीति प्रसारण में देरी, **और** संरचनात्मक असमानताओं **के चलते यह कार्य जटिल है। इससे बचने के लिए** बेहतर समन्वय, लक्षित सहायता, **और** लचीले प्रतिक्रियात्मक उपायों **वाला एक सूक्ष्म दृष्टिकोण जरूरी है, ताकि** दीर्घकालिक मुद्रास्फीति दबाव **और** सामाजिक असंतुलन **को टाला जा सके।**

UPSC Mains Practice Question

Ques : विस्तारवादी कर और ब्याज दर नीतियों के बावजूद, भारत में निजी खपत और निवेश सुस्त बना हुआ है। इस घटना के पीछे संभावित कारणों पर चर्चा करें और सुधारात्मक नीतिगत उपाय सुझाएँ। **(250 Words)**

Page : 10 : GS 2 : Social Justice

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और इसके बाद जारी UGC (भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के साथ, भारत अब विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसरों की स्थापना के लिए द्वार खोल रहा है। यू.के., ऑस्ट्रेलिया, यू.एस., इटली और कनाडा के कई संस्थान GIFT सिटी (गुजरात) और नवी मुंबई में शाखा परिसरों की स्थापना की विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं।

How will foreign universities impact higher education?

What opportunities and prospects do foreign universities see in setting up campuses in India? Why are universities abroad dependent on international students? What are some of the challenges they will face?

Pushkar

The story so far:

Several foreign universities are setting up branch campuses in India. So far seven universities from the U.K., five from Australia, and one each from the U.S., Italy and Canada are in the process of obtaining necessary approvals or have done so already. Most will be located in GIFT City and Navi Mumbai. While India has been interested in attracting foreign universities for more than a decade, the 2020 New Education Policy (NEP) revived it and the government subsequently approved the UGC (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023 (FHEI).

Why are foreign universities coming?

The countries of the Global North embarked on a massive expansion of higher education in the post-Second World War years to accommodate the growing number of young people headed to college. Over time, however, with falling birth rates, domestic enrolments started to plateau and then fall. By the early 21st century, the physical infrastructure and human capital of higher education institutions (HEIs) was too large for the diminishing numbers. This, along with cuts in public spending on higher education, started to create financial challenges. The solution was found in admitting larger numbers of international students who could be charged substantially higher tuition fees.

In 2023, international students represented 22% of total enrolments at U.K.'s universities, 24% in Australia and 30% in Canada. Though only 6% of enrolments at U.S. universities are international students, they make up for 27% of students at Ivy League schools. Universities in all "big four" host countries - Australia, Canada, the U.K. and the U.S. – have become financially reliant in varying degrees on international students. Over the past year, however, there has been a blowback. Australia and Canada have capped their international student numbers. In the U.K., new rules introduced in 2024 reduced the number of student visa applications. These restrictions are hurting universities. Redundancies have become widespread in the U.K., Australia and Canada. Therefore, many universities are looking to India to compensate for the reduced numbers of international students at their home campuses and to diversify their revenue sources.

What are some of the challenges?

India's young population and a relatively low but steadily rising gross enrolment ratio of just under 30% offers immense opportunities. However, branch campuses in other parts of the world – in China, Southeast Asia, and West and Central Asia – have a mixed record. There are several instances where they have lost money and exited. India will not be a walk in the park either.

First, India's higher education market is large in terms of student numbers – 40 million+ – but smaller in terms of the cost that an average student or family can afford. However, India is a growing economy and in the coming years, more people will be able to afford a relatively expensive college education. Second, India lacks a sufficient number of good quality HEIs. Beyond a small number of public and even fewer private institutions, the majority are average to mediocre. Branch campuses will offer better quality education than the majority of HEIs. Third, while many Indians aim to study abroad in order to emigrate, there are others who intend to work in India. Branch campuses will offer these students the option of a foreign degree at home.

The immediate to medium term impact of branch campuses can be expected to be limited. Even if a dozen or two of them are set up, their total student intake will be small. The response of Indian students to branch campuses in the first few years will be crucial to what happens next.

Pushkar is director, the International Centre Goa (Goa), Dona Paula.

THE GIST

- The countries of the Global North embarked on a massive expansion of higher education in the post-Second World War years to accommodate the growing number of young people headed to college.
- Universities in all "big four" host countries – Australia, Canada, the UK and the US — have become financially reliant in varying degrees on international students.
- India's young population and a relatively low but steadily rising gross enrolment ratio of just under 30% offers immense opportunities.

विदेशी विश्वविद्यालय भारत में क्यों रुचि दिखा रहे हैं?

1. **जनसांख्यिकीय और आर्थिक अवसर:**
   - भारत में युवाओं की आबादी अधिक है और सकल नामांकन अनुपात (GER) लगातार बढ़कर लगभग 30% हो गया है।
   - एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में निवेश करने को तैयार है।
2. **वैश्विक उत्तर (Global North) में संकट:**
   - यू.के., यू.एस., कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जन्म दर में गिरावट के कारण घरेलू नामांकन घट रहा है।
   - सार्वजनिक धन में कटौती के चलते विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं।
   - वीज़ा प्रतिबंधों और राजनीतिक प्रतिक्रिया ने पारंपरिक मेज़बान देशों में राजस्व हानि पहुँचाई है।

3. **रणनीतिक विविधीकरण:**

- भारत में परिसर खोलना विश्वविद्यालयों को आय के स्रोतों में विविधता लाने, संकाय को बनाए रखने और बुनियादी ढांचे को जारी रखने में मदद करता है।
- भारत को दीर्घकालिक, किफायती और विस्तार योग्य बाज़ार के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के लिए अवसर:

• गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में सुधार:

- अधिकांश भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान (HEIs) औसत या उससे नीचे की गुणवत्ता के हैं।
- प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश मानकों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है।

• घर पर विदेशी डिग्री:

- वे छात्र जो भारत में ही कार्य करना चाहते हैं लेकिन वैश्विक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अब उसे स्थानीय रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
- विदेश में पढ़ाई की तुलना में कम लागत इसे उच्च-मध्यम वर्ग के लिए अधिक सुलभ बनाती है।

• ब्रेन ड्रेन में संभावित कमी:

- अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की घरेलू उपलब्धता से भारत से बाहर छात्र प्रवासन में कमी आ सकती है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

1. **वित्तीय वहनशीलता (Affordability):**

- भारत में 40+ मिलियन छात्रों का बड़ा आधार है, लेकिन औसत वित्तीय क्षमता कम है।
- विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी फीस संरचना को प्रतिस्पर्धी बनाना कठिन हो सकता है।

2. **छात्र प्रतिक्रिया की अनिश्चितता:**

- कई भारतीय छात्र विदेश इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रवासन (immigration) का अवसर मिले, जो देश के भीतर शाखा परिसरों में नहीं मिल सकता।
- आरंभिक नामांकन संख्या सीमित रह सकती है, जिससे आर्थिक व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।

3. **वैश्विक अनुभव मिश्रित रहा है:**

- दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में कई विदेशी शाखा परिसरों ने खराब प्रदर्शन किया है या घाटे के कारण बंद हो गए हैं।

4. **नियामक और संचालन संबंधी बाधाएँ:**

- 2023 के दिशानिर्देशों के बावजूद, नौकरशाही और कानूनी अड़चनें बनी रह सकती हैं।
- अलग सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में **शैक्षणिक स्वायत्तता और संकाय गुणवत्ता** सुनिश्चित करना भी एक चुनौती है।

भारतीय उच्च शिक्षा के लिए निहितार्थ:

- यह पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और अनुसंधान संस्कृति में **सकारात्मक बदलाव** ला सकता है।
- प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए भारतीय HEIs को अपने **बुनियादी ढांचे और संकाय** को उन्नत करना होगा।
- इससे **नियमन, प्रत्यायन और डिग्रियों की समकक्षता** पर भी प्रश्न उठेंगे।
- यह **शैक्षिक पहुँच में विषमता** को बढ़ा सकता है — जिसका लाभ मुख्यतः **शहरी अभिजनों** को मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश एक **स्वागत योग्य सुधार** है, विशेष रूप से ऐसी प्रणाली में जो **क्षमता की कमी और गुणवत्ता की चुनौतियों** से जूझ रही है। हालांकि इसका प्रभाव **धीरे-धीरे** दिखाई देगा, जो छात्रों की प्रतिक्रिया, शुल्क संरचना और नीति की स्पष्टता पर निर्भर करेगा। दीर्घकाल में, यदि इसे **सही तरीके से प्रबंधित किया गया**, तो यह भारत को **वैश्विक उच्च शिक्षा के मानचित्र** पर स्थान दिला सकता है, साथ ही भारतीय छात्रों को **घरेलू स्तर पर अधिक विकल्प** प्रदान कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. यह विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने की अनुमति देता है।

2. यह अनिवार्य करता है कि ऐसे सभी परिसर केवल GIFT सिटी में ही स्थित होने चाहिए।

3. विनियमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पेश किया गया था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A) केवल 1 और 2

B) केवल 1 और 3

C) केवल 2 और 3

D) 1, 2 और 3

उत्तर: b)

Page : 08 Editorial Analysis

Steering the Indian economy amidst global troubles

The global economy is undergoing a significant transformation, marked by shifts in trade policies and continuing geopolitical tensions. We see a return of trade wars, the review of tariffs by countries as well as a surge in negotiations for bilateral trade agreements. These have led to heightened uncertainties, impacting not just trade but also financial markets and economic growth prospects.

With global trade dynamics evolving rapidly, it could lead to a structural realignment of global trade with long-term implications for trade and investments. Businesses will have to weigh the short-term challenges as well as long-term opportunities. Industry has to re-strategise amid rising costs, disrupted supply networks, and asymmetric information. The United States is India's largest export destination accounting for nearly one-fifth of India's merchandise exports. Therefore, uncertainties in the tariff regime in this market severely impact the business of Indian exporters. For certain sectors such as marine, apparel, carpets, gems and jewellery, pharmaceuticals, auto components, and electronics, India's dependence on the U.S. market is very high. Additional tariffs would erode margins of these exporters, particularly Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)s and make their exports unviable.

Possible issues

However, the imposition of the U.S.'s reciprocal tariffs itself remains uncertain given the possibility of interim deals and trade agreements that the U.S. is negotiating with many countries (including India) and also the recent order of the U.S. Court of International Trade challenging the imposition of reciprocal tariffs. Under such uncertain scenarios, one cannot even accurately assess whether Indian exporters will get any relative tariff advantage *vis-à-vis* competing countries such as China, Bangladesh or Vietnam that was considered a high probability in the initial assessment when reciprocal tariffs were announced. Experts and economists have highlighted that the direct impact of these tariffs (if implemented) on the Indian economy is expected to be limited due to India's resilient external economy, particularly rising contribution of services exports, high remittances, adequate forex reserves and low current account deficit. However, the uncertainties surrounding the tariffs are detrimental for exporters planning new orders and also their impact on decision making. In addition, there is a risk of increased threat of dumping into India by China and the Association of Southeast Asian Nations looking to redirect their surplus production.

Harsha Vardhan Agarwal

is President, The Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)

Industry needs to re-strategise amidst rising costs, disrupted supply networks and asymmetric information

Medium- to long-term opportunity

Despite the global headwinds, India stands to benefit with the right strategy. The global restructuring of trade offers India an opportunity to become an integral part of the renewed global supply chains. India needs a three-pronged strategy – to manage external shocks; to ensure domestic economic resilience and to leverage a window of opportunity to enhance its global exports. These key policy actions can be considered. First, India has taken a proactive approach by engaging early in Bilateral Trade Agreement (BTA) negotiations with the U.S. Being the first to conclude such an agreement could give India a first-mover advantage. The BTA must be crafted to ensure zero tariffs on sectors critical to India's interests, while cautiously opening up areas without compromising national priorities. India's service exports to the U.S. remain robust and it must be ensured that these are not impacted. Liberalisation of tariffs with the U.S. should be approached on a strictly bilateral basis. Addressing non-tariff barriers (NTBs) will be critical. Possibilities of mutual recognition agreements must be explored. A swift yet balanced trade deal will be key.

Second, the conclusion of an FTA with the U.K. is a huge positive. India must now pursue other key FTAs with equal vigour. The early conclusion of an FTA with the European Union , Comprehensive Economic Cooperation Agreement with Australia and other important partners will offer Indian exporters enhanced market access in alternative markets.

Third, strengthening import monitoring mechanisms becomes important in wake of a greater risk of dumping into India. Trade remedial measures should be deployed swiftly to protect domestic industries from economic damage.

Fourth, sustaining public capital expenditure is vital in maintaining growth momentum amid global headwinds. Continued public capex will ensure that the domestic economy remains resilient and also help to crowd-in private investments over the medium term.

Fifth, monetary policy should continue to remain accommodative. With inflation currently under control and projected to be lower in coming quarters, further rate cuts by the Reserve Bank of India will help propel growth.

Sixth, anchor potential foreign investments across sectors looking to diversify their supply chains from China, Vietnam and other countries. A focused approach would be required to target global companies to set up shop in India.

Expedite reforms

Finally, work towards next generation reforms and regulatory reforms – as proposed in the last two Union Budgets – must be expedited. Production-Linked Incentive (PLI) schemes must be expanded to include other potential sectors (e.g., hearables and wearables, IoT devices, battery raw materials). These will help scale up manufacturing, attract investment in critical sectors, and build self-reliance.

While global uncertainties pose undeniable challenges, they also offer an opportunity for India to emerge as a global manufacturing hub and be an integral part of the global supply chains. Through strategic trade negotiations and structural reforms, India can weather the storm and emerge stronger.

Paper 03 : Indian Economy

UPSC Mains Practice Question : भारत को तेजी से संरक्षणवादी होते वैश्विक माहौल में अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए व्यापार कूटनीति का लाभ उठाना चाहिए। उभरती वैश्विक व्यापार नीतियों और द्विपक्षीय वार्ताओं के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 words)

Context :

वैश्विक अर्थव्यवस्था कई प्रकार के व्यवधानों का सामना कर रही है — भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार युद्धों से लेकर शुल्क की अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्संरेखण तक। इन चुनौतियों का भारत के निर्यात क्षेत्र, विदेशी व्यापार नीति और घरेलू आर्थिक लचीलापन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में, फिक्की (FICCI) के अध्यक्ष ने बाहरी झटकों से निपटने और उभरते वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक बहु-आयामी रोडमैप प्रस्तुत किया है।

वैश्विक परिदृश्य:

- संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा प्रतिपालक शुल्क (reciprocal tariffs) और व्यापार प्रतिबंध।
- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों (BTAs) के लिए निरंतर शुल्क समीक्षा और प्रयास।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती अनिश्चितता, जिससे MSMEs और अमेरिका जैसे उच्च लागत वाले गंतव्यों पर निर्भर निर्यातकों पर प्रभाव।
- चीन और ASEAN जैसे अधिशेष उत्पादन करने वाले देशों द्वारा भारत में डंपिंग के खतरे में वृद्धि।

भारत के लिए जोखिम:

1. **निर्यात की संवेदनशीलता:**
   - अमेरिका भारत के माल निर्यात का लगभग 20% आयात करता है, विशेषकर फार्मा, परिधान, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में।
   - शुल्क वृद्धि या व्यापार समझौतों में देरी से MSME की लाभप्रदता और निर्यात व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।
2. **वैश्विक प्रभाव (स्पिलओवर):**
   - व्यापार की अनिश्चितताओं से व्यापारिक विश्वास, निवेश प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखला के निर्णय प्रभावित होते हैं।
   - चीन और ASEAN देशों की ओर से भारत में डंपिंग की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वे वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रहे हैं।
3. **घरेलू अनिश्चितता:**
   - निर्यातकों को शुल्क व्यवस्थाओं और गैर-शुल्क बाधाओं (NTBs) की स्पष्टता की कमी के कारण योजना बनाने में कठिनाई होती है।
   - कुछ बाज़ारों और क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता से दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ सकता है।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया:

1. **स्मार्ट व्यापार कूटनीति:**
   - अमेरिका और यू.के. के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाना।
   - प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शून्य शुल्क सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा।
   - गैर-शुल्क बाधाओं से निपटने के लिए म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स (MRAs) और नियामक समरूपता को बढ़ावा देना।

2. **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:**
   - यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया (CECA) और अन्य संभावित साझेदारों के साथ FTAs को अंतिम रूप देना।
   - अमेरिका जैसे एकल देश बाजारों पर निर्भरता को कम करके वैश्विक पहुंच बढ़ाना।
3. **रक्षात्मक व्यापार उपाय:**
   - आयात निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क जैसे उपाय अपनाना।
   - अचानक आयात में वृद्धि के कारण आर्थिक विघटन से बचाव।
4. **घरेलू मांग और पूंजीगत व्यय (Capex) को प्रोत्साहन:**
   - आर्थिक वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को जारी रखना।
   - स्थायी सरकारी खर्च के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करना (Crowding-in effect)।
5. **मौद्रिक नीति का संरेखण:**
   - मुद्रास्फीति नियंत्रित होने की स्थिति में लचीली (accommodative) मौद्रिक नीति बनाए रखना।
   - वैश्विक मंदी के बीच ब्याज दरों में और कटौती से विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है।
6. **विदेशी निवेश आकर्षित करना:**
   - चीन से आपूर्ति श्रृंखला को हटाने की योजना बना रही वैश्विक कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करना।
   - प्रोत्साहनों और सरल स्वीकृति प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
7. **संरचनात्मक सुधार:**
   - केंद्रीय बजट में प्रस्तावित अगली पीढ़ी के सुधारों को तेजी से लागू करना।
   - उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को IoT, बैटरी खनिज, वियरेबल्स जैसे उच्च संभावनाशील क्षेत्रों तक विस्तार देना।
   - व्यापार करने की आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ाने के लिए नियामक सरलीकरण को आगे बढ़ाना।

निष्कर्ष:

हालांकि वैश्विक व्यापार में बाधाएँ अल्पकालिक रूप से महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं, वे भारत के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक अवसर भी प्रदान करती हैं। लक्ष्य आधारित व्यापार समझौतों, गहरे संरचनात्मक सुधारों, और घरेलू आर्थिक लचीलापन को सुदृढ़ करने के माध्यम से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को एक प्रमुख केंद्र के रूप में पुनःस्थापित कर सकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत केवल एक प्रतिक्रियात्मक सहभागी न बने, बल्कि एक सक्रिय वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में उभरे।